भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3575
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय

†3575. **श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
श्रीमती भारती पारधी:
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा संस्थानों में बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रगति कितनी है;
(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत परिकल्पित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शीर्ष रैंकिंग वाले वैश्विक विश्वविद्यालयों के प्रवेश को सुगम बना रही है, साथ ही देश के सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्ग के छात्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, के लिए समान पहुँच सुनिश्चित कर रही है; और
(ग) देश भर में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा में हाशिए पर रहने वाले वर्ग के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, सरकार ने शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि हेतु 12926.10 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसमें रूसा के पहले चरणों की प्रतिबद्ध देयता भी शामिल हैं। पीएम-उषा के बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) घटक के अंतर्गत 35 विश्वविद्यालयों (मध्य प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय और महाराष्ट्र में 4 विश्वविद्यालय सहित) को अनुमोदित किया गया है।

विद्यार्थियों की सुगम गतिशीलता और क्रेडिट अंतरण को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) पहल की शुरूआत की है। एबीसी क्रेडिट मान्यता, संचयन और अंतरण को औपचारिक रूप देने में सहायता करता है। एबीसी प्रणाली के

अंतर्गत, शिक्षा परितंत्र के हितधारकों के बीच सहज संवाद और शिक्षार्थियों की जीवनपर्यन्त यात्रा को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए 12 अंकों की विशिष्ट पहचानकर्ता, स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर) आईडी तैयार की गई है।

(ख)*:* राष्ट्रीय शिक्षा नीति *2020* के अनुरूप, यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एफएचईआई) के परिसरों की स्थापना को सहज करने के लिए नवंबर, *2023* में '*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम*, 2023' जारी किए हैं। ये विनियम *https://fhei.ugc.ac.in/Downloads/Regulations.pdf* पर उपलब्ध हैं।

विनियमन 2023 के अंतर्गत, यूजीसी ने ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की 12 विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को भारत में गुरुग्राम (हरियाणा), बेंगलुरु (कर्नाटक), मुंबई (महाराष्ट्र), चेन्नई (तमिलनाडु) और नोएडा/ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) सहित विभिन्न स्थानों पर अपने परिसर खोलने के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय पहले ही गुरुग्राम, हरियाणा में अपना परिसर स्थापित कर चुका है।

इसके अतिरिक्त, विश्व-स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थाएं अक्टूबर, 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार गिफ्ट सिटी में अपने शाखा परिसर स्थापित कर सकते हैं। ये विनियम https://ifsca.gov.in/Document/Legal/ifsca-ibc-and-oec-regulations-20221310202211363 9.pdf पर उपलब्ध हैं।

डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय नामक दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने अपतटीय शाखा परिसर स्थापित किए हैं और उपर्युक्त विनियम**,** 2022 के अंतर्गत गिफ्ट सिटी**,** गुजरात में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

(ग): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) *2022-23 (*अनंतिम) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) *29.5* है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में जीईआर को बढ़ाने के लिए अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थाएं खोलना*;* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों सहित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करना*;* उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आवश्यकतानुसार निकास के साथ-साथ पुनः प्रवेश का विकल्प प्रदान करना*;* युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन (स्वयं) मंच के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों के लिए किसी भी समय, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना*;* और विद्यार्थियों, विशेष रूप से स्थानीय/ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए *13* भाषाओं में जेईई, नीट (यूजी) और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) परीक्षा आयोजित करना जैसे विभिन्न प्रयास किए हैं।

*****